देश के सभी राज्यों में क्रियान्वित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसे कब से क्रियान्वित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

फसल ऋण प्रणाली की कार्यान्विति में हुई प्रगति

1.	आन्ध्र प्रदेश	खरीफ 1966 से लागू की गई है ।
2.	असम	सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा अधिक पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम के क्षेत्रों में शुरूआत की गई है ।
3.	बिहार	सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा अधिक पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम के क्षेत्रों में शुरूआत की गई है । इस योजना को खरीफ 1967 से राज्य भर में लागू किया जाना है ।
4.	गुजरात	फसल ऋण प्रणाली लम्बे अर्से से लागू है ।
5.	जम्मू तथा काश्मीर	सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा अधिक पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम के क्षेत्रों में शुरूआत की गई है ।
6.	केरल	रबी 1966 से कार्यान्वित की गई है ।
7.	मद्रास	फसल ऋण प्रणाली संशोधित रूप में लागू है ।
8.	मध्य प्रदेश	कुछ जिलों में खरीफ 1966 से तथा अन्य जिलों में रबी 1966 से कार्यान्वित की गई है ।
9.	मैसूर	कुछ जिलों में खरीफ 1966 से लागू की गई है ।
10.	महाराष्ट्र	फसल ऋण प्रणाली लम्बे अर्से से लागू है ।
11.	उड़ीसा	चुने हुए जिलों में रबी 1966 में आंशिक तौर पर लागू की गई है और खरीफ, 1967 से राज्य भर में लागू की जा रही है ।
12.	पंजाब तथा हरियाणा	यह योजना संशोधित रूप में खरीफ 1966 से लागू की गई है ।
13.	राजस्थान	खरीफ 1966 से लागू की गई है ।
14.	उत्तर प्रदेश	अधिक पैदावार वाली किस्मों के क्षेत्रों में खरीफ 1966 से लागू की गई है और अन्य क्षेत्रों में खरीफ 1967 से लागू की जा रही है ।
15.	पश्चिमी बंगाल	दो जिलों में खरीफ 1966 से आंशिक तौर पर लागू की गई है और खरीफ 1967 से सारे राज्य में लागू की जा रही है ।
16.	नागालैण्ड	इस प्रणाली को लागू करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Collection of Road Tax Fees in Delhi

1562. Shri D. N. Deb: Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to allow vehicle owners in Delhi to

deposit their Road tax fees in the Post Offices in Delhi; and

(b) if so, when the scheme is likely to be put into operation?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The Delhi administration is considering a proposal to collect tax on all motor vehicles registered in Delhi through the post offices.

(b) As the administrative and other implications of the proposal have still to be worked out, it is not possible at this stage to say when it will be put into operation.

Fish Supply to West Bengal

1504. Dr. Ranen Sen: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount of fish supplied to West Bengal by the Fish Corporation of India set up by the Central Government between December, 1965 and December, 1968?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): The amount of fish supplied to West Bengal by the Central Fisheries Corporation during the period from December, 1965 to December, 1968 is 8,19,047 Kgs.

पटना में गंगा नदी पर पुल

1505. श्री वाल्मीकि चौधरी : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव कब रखा गया था और क्या उस समय पुल की लागत का अनुमान लगाया गया था;

(ख) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तावित पुल के निर्माण पर कितनी बार विचार किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि जब भी प्रस्ताव पर विचार किया गया, प्रत्येक अवसर पर पुल की अनुमानित लागत अधिक लगाई गई; और

(घ) पुल की अनुमानित लागत कितनी लगाई गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है । अतः इस परियोजना से संबद्ध समस्त मामलों में बिहार सरकार संबंधित है । इस पुल के निर्माण की स्कीम का राज्य के इंजीनियरों द्वारा 1940 से अध्ययन और जांच की जा रही है । वे अभी तक किसी स्कीम को अन्तिम-रूप देने में सफल नहीं हो सके हैं क्योंकि वह एक उपयुक्त स्थान के चुनाव पर निर्भर करती है जिसकी अभी जांच की जा रही है । अभी हाल ही में राज्य सरकार ने सूचित किया था कि पुल में 25 करोड़ रुपये लग सकते हैं । इसके पहले राज्य सरकार से लागत का कोई प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ था ।

चावल का आयात

1506. श्री वाल्मीकि चौधरी :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में सरकार का विचार विदेशों से चावल आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इसके लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की मुक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है ।